हर जगह इस बात के कई संकेत मिल रहे हैं कि भारत लगातार नौकरियों के संकट से जूझ रहा है। आधिकारिक डेटा स्रोत और साथ ही कई जमीनी रिपोर्टें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं। इस संकट के व्यापक आर्थिक कारण क्या हैं?

कम श्रम मांग के लक्षण

शुरुआत में, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित दो प्रकार के रोजगार के बीच अंतर करना उपयोगी होगा। पहला वेतन रोजगार है जो नियोक्ताओं द्वारा मुनाफे की तलाश में मांगे गए श्रम का परिणाम है। दूसरा स्व-रोजगार है जहां श्रम आपूर्ति और श्रम मांग समान हैं, यानी, कार्यकर्ता खुद को रोजगार देता है। वेतनभोगी श्रम और नौकरियों के बीच एक और उपयोगी अंतर भी किया जा सकता है। पहले में एक नियोक्ता के लिए किए गए सभी प्रकार के श्रम शामिल हैं, जिसमें एक चरम पर दैनिक मजदूरी का काम और दूसरे पर अत्यधिक भुगतान वाली कॉर्पोरेट नौकरियां शामिल हैं। लेकिन, नौकरियाँ आम तौर पर अपेक्षाकृत बेहतर भुगतान वाली नियमित मजदूरी या वेतनभोगी रोजगार को संदर्भित करती हैं। दूसरे शब्दों में, सभी नौकरियाँ दिहाड़ी श्रम हैं, लेकिन सभी दिहाड़ी श्रम को नौकरियाँ नहीं कहा जा सकता। जब हम नौकरियों की समस्या की बात करते हैं, तो हम विशेष रूप से नियमित वेतन वाले काम के लिए अपर्याप्त श्रम मांग की बात कर रहे होते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक रूप से खुली बेरोजगारी (काम से बाहर नौकरी चाहने वालों) के साथ-साथ स्व-रोजगार के साथ-साथ आकस्मिक वेतन वाले श्रमिकों सहित अनौपचारिक रोजगार के उच्च स्तर की उपस्थिति की विशेषता रही है। उत्तरार्द्ध को ष्प्रच्छन्न बेरोजगारीष् भी कहा जाता है क्योंकि, खुली बेरोजगारी के समान होने के कारण, यह औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी को भी इंगित करता है।

अवसरों की यह कमी पिछले चार दशकों में गैर-कृषि क्षेत्र में वेतनभोगी श्रमिकों की कमोबेश स्थिर रोजगार वृद्धि दर से परिलक्षित होती है। औपचारिक क्षेत्र की श्रम मांग में ऐसी बाधाओं की क्या व्याख्या है?

औपचारिक गैर-कृषि क्षेत्र में श्रम की मांग दो अलग-अलग कारकों द्वारा निर्धारित होती है। सबसे पहले, चूंकि औपचारिक क्षेत्र की कंपनियां लाभ के लिए उत्पादन का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करती हैं, इसलिए श्रम की मांग उस उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है जिसे कंपनियां बेचने में सक्षम हैं। तकनीकी विकास के किसी भी स्तर के तहत, उत्पादन की मांग बढ़ने पर औपचारिक क्षेत्र में श्रम की मांग बढ़ जाती है। दूसरा, श्रम की मांग प्रौद्योगिकी की स्थिति पर निर्भर करती है जो उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कंपनियों को कितने श्रमिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता तय करती है। श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों का परिचय कंपनियों को कम संख्या में श्रमिकों को काम पर रखकर समान मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।

चूँकि आर्थिक नीति आम तौर पर आउटपुट के स्तर के बजाय आउटपुट वृद्धि (जीडीपी या मूल्य-वर्धित के बारे में सोचें) के संदर्भ में तैयार की जाती है, आइए हम विकास दर के संदर्भ में इस तर्क की जांच करें। रोजगार वृद्धि दर दो कारकों की सापेक्ष शक्ति से निर्धारित होती है - उत्पादन वृद्धि दर और श्रम उत्पादकता वृद्धि दर (प्रति श्रमिक उत्पादन की वृद्धि दर)। यदि श्रम उत्पाद. कता वृद्धि दर नहीं बदलती है, तो उच्च उत्पादन वृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर को बढ़ा देती है। दूसरे शब्दों में, उच्च आर्थिक विकास

को बढ़ावा देने वाली नीतियां उच्च रोजगार वृद्धि भी हासिल करेंगी। दूसरी ओर, यदि श्रम उत्पादकता वृद्धि दर बढ़ती है, तो रोजगार वृद्धि दर किसी दिए गए उत्पादन वृद्धि दर से कम हो जाती है।

भारत में, 1980 और 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और मूल्य वर्धित विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद औपचारिक और गैर-कृषि क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर अनुत्तरदायी रही। उत्पादन वृद्धि दर में परिवर्तन के प्रति रोजगार वृद्धि दर की प्रतिक्रियाशीलता की कमी रोजगारविहीन वृद्धि की घटना को दर्शाती है। यह श्रम उत्पादकता वृद्धि दर और उत्पादन वृद्धि दर के बीच एक मजबूत संबंध को इंगित करता है। ऐसा क्यों होना चाहिए?

भारतीय विशेषताओं के साथ रोजगार रहित विकास

जैसे-जैसे कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आम तौर पर देखा जाता है कि वह अधिक उत्पादक भी हो जाती है। अर्थात, कुल उत्पादन की अधिक मात्रा का उत्पादन करने की प्रक्रिया में, कंपनियाँ प्रति कर्मचारी अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है जिसे अर्थशास्त्री ष्पैमाने की अर्थव्यवस्थाष् कहते हैं। चूँकि कंपनियाँ अधिक उत्पादन करती हैं, इसलिए उन्हें श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाना आसान लगता है। लेकिन श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों को किस हद तक पेश किया जाता है यह श्रम की सौदेबाजी की शक्ति पर निर्भर करता है।

हम उत्पादन वृद्धि और श्रम उत्पादकता वृद्धि के बीच संबंध की मजबूती के आधार पर दो प्रकार की बेरोजगार विकास व्यवस्थाओं के बीच अंतर कर सकते हैं।

पहले मामले में, श्रम उत्पादकता वृद्धि दर की उत्पादन वृद्धि दर के प्रति प्रतिक्रिया कमजोर है। इस मामले में बेरोजगार विकास की संभावना विशेष रूप से स्वचालन और श्रम-बचत प्रौद्योगिकी की शुरूआत के कारण उभरती है। लेकिन यदि उत्पादन वृद्धि दर बढ़ती है तो ऐसी व्यवस्थाओं में रोजगार वृद्धि दर अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। श्रम उत्पादकता की कमजोर प्रतिक्रिया के तहत, रोजगार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का सकारात्मक प्रभाव श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों के प्रतिकूल प्रभाव पर हावी होगा। यहां, नौकरियों के संकट का समाधान सिर्फ और अधिक तीव्र आर्थिक विकास है।

दूसरे मामले में, जो कि भारतीय मामला है, उत्पादन वृद्धि दर के प्रति श्रम उत्पादकता वृद्धि दर की प्रतिक्रिया अधिक है। यहां, रोजगार पर उत्पादन वृद्धि दर का सकारात्मक प्रभाव श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों के प्रतिकूल प्रभाव का प्रतिकार करने में विफल रहता है। ऐसे शासनों में रोजगार वृद्धि दर को केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता है। श्रम उत्पादकता वृद्धि दर किस हद तक उत्पादन वृद्धि दर पर प्रतिक्रिया करती है, यह कलडोर-वरडॉर्न गुणांक द्वारा परिलक्षित होता है। हाल के वर्किंग पेपर (हमारे द्वारा) में, हम दिखाते हैं कि भारत के गैर-कृषि क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों की तुलना में औसत कलडोर-वर्डोर्न गुणांक की तुलना में अधिक विशेषता है। यह भारत में बेरोजगार विकास व्यवस्था का यह विशिष्ट रूप है जो भारत की व्यापक आर्थिक नीति चुनौती को अन्य देशों से गुणात्मक रूप से अलग बनाता है।

व्यापक आर्थिक नीति ढांचा

मैक्रोइकॉनॉमिक्स में कीनेसियन क्रांति का केंद्रीय योगदान रोजगार पर बाध्यकारी बाधा के रूप में समग्र मांग की भूमिका को उजागर करना था। ऐसा माना गया कि राजकोषीय नीति उत्पादन को प्रोत्साहित करके श्रम मांग को बढ़ाएगी। जिन विकासशील देशों को अपनी स्वतंत्रता के दौरान दोहरी अर्थव्यवस्था संरचना विरासत में मिली, उन्हें उत्पादन पर अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ा। महालनोबिस रणनीति ने भारी औद्योगीकरण की नीति को आगे बढ़ाते हुए, उत्पादन और रोजगार पर बाध्यकारी बाधा के रूप में पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता की पहचान की। विकासशील देशों के अनुभवों पर आधारित संरचनावादी सिद्धांतों ने कृषि बाधा और भुगतान संतुलन की बाधाओं की संभावना पर प्रकाश डाला। इन दोनों बाधाओं के कारण भारत में प्रमुख नीतिगत बहसें हुईं, विशेषकर 1970 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में।

बहरहाल, इन सभी अलग-अलग रूपरेखाओं में जो सामान्य बात रही वह यह धारणा थी कि गैर-कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि दर बढ़ाना औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर बढ़ाने के लिए पर्याप्त शर्त होगी। लेकिन सबूत बताते हैं कि रोजगार की चुनौती को अब केवल तेज जीडीपी वृद्धि के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता है। बल्कि, जीडीपी वृद्धि पर ध्यान देने के साथ-साथ रोजगार पर भी एक अलग नीतिगत फोकस की आवश्यकता है।

ऐसी रोजगार नीतियों के लिए मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों घटकों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, भारत में कंपनियों को पर्याप्त कुशल श्रम की कमी के कारण स्वचालित करना आसान लगता है, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर

सार्वजनिक प्रावधान के माध्यम से कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ कौशल अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। मांग पक्ष पर, प्रत्यक्ष सार्वजनिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी।

ऋण-स्थिरता को बनाए रखते हुए ऐसे व्ययों को वित्तपोषित करने के लिए वर्तमान व्यापक आर्थिक ढांचे को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनः उन्मुख करने की आवश्यकता है, जिसमें छूट को कम करके और अनुपालन में सुधार करके जीडीपी अनुपात में प्रत्यक्ष कर को बढ़ाना और रचनात्मक रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए मैक्रो-नीति का अधिक कल्पनाशील उपयोग शामिल है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वेतन रोजगार: नियोक्ताओं द्वारा मुनाफे की तलाश में मांगे गए श्रम का परिणाम होता है।
2. स्व-रोजगार : जहां श्रम आपूर्ति और श्रम मांग समान होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to employment:

1. Wage employment: results from labor sought by employers in the pursuit of profits.
2. Self-Employment: Where labor supply and labor demand are equal.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत में रोजगार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है तथा औपचारिक क्षेत्र की श्रम मांग में मौजूद बाधाओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में रोजगार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में औपचारिक क्षेत्र की श्रम मांग में मौजूद बाधाओं की चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।